भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2993

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

सीसीयूएस परियोजनाएं

†2993. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय बजट 2026 में घोषित कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज (सीसीयूएस) पहलों के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए किसी मानकीकृत निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन ढांचे को अधिसूचित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में सीसीयूएस प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण को जारी करने या जारी रखने से पहले स्वतंत्र तृतीय पक्ष संपरीक्षा अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने सीसीयूएस परियोजनाओं से जुड़े निवल कार्बन कटौती, भंडारण के स्थायित्व और जीवनचक्र उत्सर्जन का आकलन करने के लिए कोई कार्यप्रणाली निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीसीयूएस से संबंधित निधि के आवंटन, परियोजना-वार उत्सर्जन आंकड़ों और संपरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में कोई सार्वजनिक प्रकटीकरण तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने सीसीयूएस से जुड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के अंतर्गत कार्बन ऑफसेट की दोहरी गिनती अथवा गलत सूचना देने को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय स्थापित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ङ) : बजट (वित्तीय वर्ष 2026-27) की घोषणा के अनुसार, कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (सीसीयूएस) प्रौद्योगिकियों के लिए अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य पांच औद्योगिक क्षेत्रों, अर्थात विद्युत, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी तथा रसायन में अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में उच्च तत्परता स्तर प्राप्त करने के लिए इन प्रौद्योगिकियों के बड़े पैमाने पर विकास को बढ़ावा देना है।

सीसीयूएस कार्यक्रम वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में स्थापना के चरण में है। सीसीयूएस कार्यक्रम के अनुमोदन के बाद, मंत्रालय आवश्यक नियम/दिशानिर्देश तैयार करेगा; जिसमें मानक, निगरानी, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन तंत्र, परियोजना चयन मानदंड, लेखा परीक्षा आवश्यकताएं, सार्वजनिक प्रकटीकरण तंत्र, कार्बन कटौती का आकलन/रिपोर्ट करने की पद्धति और कार्यान्वयन से संबंधित अन्य पहलू शामिल हैं।

****